मालगाड़ी की 24 कि.मी. प्रति घंटा है, जो ट्रैक्टर की गति के बराबर है, जबकि बजट में सुपरसोनिक गति के सपने दिखाए गए हैं। बजट घोषणाएं जन-मानस को सतही तौर पर प्रफुल्लित कर सकती हैं, परन्तु देश का स्वरूप बदलने में सक्षम नहीं है। 25 रुपए में मासिक पास देना प्रशंसनीय है, परन्तु गाड़ी में बैठने का स्थान उपलब्ध कराना उससे भी जरूरी है। दैनिक सवारी डिब्बों में यात्री भेड़-बकरियों की तरह भरे जाते हैं। सरकार को इस पहलू पर भी ध्यान देना चाहिए। माल गाड़ी के डिब्बे केवल मोटे उत्पाद जैसे कोयला, सीमेंट, लोहा, खाद आदि ढोने के योग्य हैं। इसीलिए माल भाड़े का 45 प्रतिशत भाड़ा केवल कोयला ढुलाई से आता है। मालगाड़ियों के डिब्बों को अन्य उत्पादों की ढुलाई के अनुरूप बदलने एवं व्यापारियों की सुविधा के अनुसार सेवा सुनिश्चित करना आवश्यक है।

उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह रेल ढांचे को इक्कसवीं सदी की आवश्यकता के अनुरूप बढ़ाए बदले एवं आधुनिकीकरण करे। धन्यवाद।

Demand to provide medical help to cure the people suffering from an unidentified disease in Kandhamal District of Orissa

SHRI RAMA CHANDRA KHUNTIA (Orissa): Sir, thirteen persons including eleven children died in Daring Badi of Kandhamal district in Orissa suffering from an unidentified disease. About hundred more are affected. The State Health Department is unable to control the disease and is saying that it could be Malaria or some sort of fever. It is spreading like wild fire from one village to another. This part is also affected by Naxal violence. Neither the affected people are willing to go to the Daring Badi Health centre nor the mobile health centre is reaching the affected persons. The situation is very alarming.

I urge upon the Government to send a team of doctors with sufficient medicine and CRPF police protection to help the affected persons in Daring Badi in Kandhamal district of Orissa.

Demand to withhold disinvestment in Coal India Limited

श्री आर.सी. सिंह (पश्चिमी बंगाल) : सर, मैं बड़े दुख और अफसोस के साथ इस माननीय सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि Coal India Limited Company और देशवासियों के विरोध के बावजूद कोयला मंत्री Coal India Limited में विनिवेश करने पर आमादा हैं। कल और परसों मीडिया में भी यह खबर आई है कि CIL में 10 प्रतिशत शेयर का विनिवेश करने के लिए कोयला मंत्रालय प्रधान मंत्री से शीघ्र मंजूरी लेगा। मंत्री जी का कहना है कि कम्पनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस संबंध में अपनी संस्तुति दी है। वास्तविक सच्चाई यह है कि CIL के बोर्ड पर ऐसा प्रस्ताव पारित करने के लिए दबाव डाला जा रहा है। यह कम्पनी, उसके कर्मचारी और देश हित में नहीं है। हम CIL में किसी भी तरह के विनिवेश का विरोध करते हैं। CIL एक नवरत्न कम्पनी है और पिछले साल इसने 8700 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है।

सर, जब संसद का सत्र चल रहा हो, तो यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी तरह के पॉलिसी डिसीज़न के बारे में सबसे पहले संसद को सूचित करे, लेकिन संसद की अवहेलना करके कोयला मंत्रालय ने यह प्रस्ताव बनाया है और शीघ्र ही यह उसे वित्त मंत्रालय की अनुमति के लिए भेज रहा है।

सर, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं और अपील करता हूं कि वह CIL में विनिवेश न करे। यह न केवल इस कम्पनी के हितों के विरुद्ध है, बल्कि देश और देशवासियों के हित में भी नहीं है।